International Indexed, Refereed Research Journal, ISSN -2250-253X, (Print), E-ISSN 2320-544X, Issued – 8, Vol- I, August, 2013

शोध पत्र- हिन्दी

उच्चशिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश : एक ऑकलन

* डॉ. प्रवीण शर्मा

* सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, श्री अटलबिहारी वाजपेयी शा. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर , म.प्र.

21 वीं सदी के भारत में उच्च शिक्षा के विस्तार की न केवल आवश्यकता है वरन् पूर्व से स्थापित उच्चशिक्षा संस्थानों के नवीनीकरण, अद्यतन एवं उन्नयन के त्वरित कदम शीघ्र उठाने के प्रयासों की भी आवश्यकता है । भारतीय उच्च शिक्षा जगत से निकला युवा आज अपनी क्षमताओं और ज्ञान से न केवल विश्व जगत को प्रभावित कर रहा है, बल्कि विश्व के कई बड़े तकनीकी वैज्ञानिक संस्थानों में उच्च पदों पर अपनी योग्यता का लोहा मनवाकर उन्हे सुशोभित कर रहा है ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पुनः अपने उद्बोधन में अमेरिकी युवाओं को चेतावनी दी है कि ''अमेरिकी युवाओं को मुख्य रूप से भारतीय छात्रों से अपने आपको प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रखना होगा।'' (15 मई 2013)

Hkkjr e orZeku e mPp f'k{kk dk ifjn`'; %&

भारत शासन ने वर्ष 2020 तक भारत को एक विकसित देश (Developed Country) के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है । Hkkjrh; mPp f'k{kk 0;oLFkk vefjdk d cknfo'o dh nljh lcl cMh 0;oLFkk g] इस व्यवस्था की निगरानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित 12 स्वायत्तशासी संस्थाओं के द्वारा की जाती है । इस व्यवस्था में वर्ष 2001 से 2011 के एक दशक में 20,000 महाविद्यालय व 8 लाख से अधिक विद्यार्थी और शामिल हो गए है । उच्चशिक्षा के क्षैत्र में नामांकन दर वर्ष 2005–06में 11. 5%, वर्ष 2009–10में15% वर्ष 2010–11में16% थी ।इस प्रकार संकायवार नामांकन दर में उल्लेखनीय वृध्दि दर्ज की गई है। भारत में वर्तमान में कुल 568 विश्वविद्यालय है जिनका विवरण देखें तालिका क्रं. (1) में दर्शाया गया है :–

भारत शासन द्वारा उच्चशिक्षा पर किए जाने वाले व्यय में भी निरंतर वृद्धि की जा रही है जहॉ यह 1950–51 में 49% था, वर्तमान में इसमें लगभग 90% तक की वृद्धि की गई है । यह उल्लेखनीय है कि इतने आकर्षक ऑकड़ों के बावजूद इस सम्पूर्ण व्यय का लाभ मात्र 6 प्रतिशत संबंधित आयु वर्ग को ही प्राप्त हो पाता है। जबकि तुलनात्मक रूप से विदेशों (विकसित देशों) में 80 प्रतिशत आयु वर्ग को यह सुविधा प्राप्त हो जाती है । हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या पुनः इस विकास को हजम कर जाती है । यह कटु सत्य है कि विकासशील राष्ट्रों के लिए, विकसित राष्ट्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की तुलना में इस प्रकार की खाई को पाटना आसान नहीं होता है ।

mPp f'k{kk ekx o ifr %

भारत में वर्ष 2004 उच्च शिक्षा जगत में एक मील का पत्थर साबित हुआ है क्योंकि o"k 2004 rduhdh lLFkkvk d foLrkj dk o"k jgk g A दूरस्थ शिक्षा व खुले विश्वविद्यालय भी भारतीय उच्च शिक्षा के मुख्य लक्षण है । इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय है, जिसमें लगभग सम्पूर्ण विश्व के 3.5 लाख विद्यार्थी शामिल है ।

उच्च शिक्षा भारत में अपने उत्कर्ष की ओर अग्रसर है। हमारे यहॉ विश्व के नामचीन **IIM** o **IIT** lLFkku है । इस संस्थानों में न केवल भारतीय वरन् बड़ी संख्या में विदेशी छात्र भी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रतिवर्ष आते है। भारतीय व्यवसायिक ¼**Prtofessionals**½ शिक्षित व्यक्तियों की आज सम्पूर्ण विश्व में मांग है, यह भारतीय शैक्षणिक जगत की आन्तरिक शक्ति का परिचायक है। निजी क्षेत्र व शासकीय व्ययों पर संचालित ch Ldy भी यहां है। **IIM** lLFkku vkt mRd"Vrk d dUn cu x, g A cgjk"Vh; dEiuh o fuxe {k=

तालिका क्रं. (1) Hkkjr e fo'ofo|ky;k dh fLFkfr (वर्ष 2011–12)

Ø-	fo'ofo|ky;@lLFkku dk idkj@egkfo|ky;	fo'ofo|ky;@lLFkk dh l[;k		
1	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	152		
2	राज्य विश्वविद्यालय	315		
3	डीम्ड विश्वविद्यालय	129		
4	निजी विश्वविद्यालय	191		
5	राष्ट्रीय महत्व के राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित/कार्यरत संस्थान	33		
6	महाविद्यालय स्वा. निजी	33023		
7.	8. 9. महिला महाविद्यालय केन्दीय महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय	800	669	1324

(स्त्रोत : FICCI&EY:higed.in govt.twelth five year pln.12-17; &page10½

में इनके विद्यार्थियों की अच्छी मांग है । सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की वर्तमान नामांकन दर को 12.4% से बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य रखा गया है जिसे प्राप्त करने के लिए आगामी 8 वर्षों में 40,000 से अधिक महाविद्यालय तथा 800 से 1000 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता होगी एवं जिसके पूंजीगत व संचालन व्यय सहित लगभग 9.50 लाख करोड़ रूपये अतिरिक्त विनियोजन करना होगा। इस मांग व पूर्ति के अंतराल को कम करना होगा।

Hkkjrh; mPp f'k{kk m|kx dk pqukSfr;k¡ %&

वर्तमान समय में शिक्षण एक व्यापार बन गया है, अकादमिक वर्श 2010–11 में लगभग 14 yk[k fo|kfFk;k¡ ने संपूर्ण भारत में नामांकन उच्च हेतु करवाया, जबकि लगभग 62]000 f'k{kd संख्या संबंधित वर्ष में दर्ज की गई । लेकिन इसके बावजूद वर्तमान में मात्र **20%** उच्च शिक्षण संस्थान ही xzkeh.k {ks= esa dk;Zjr है एवं शेष 80% शिक्षण संस्थान शहरी व अर्द्धशहरी क्षेत्रों में कार्यरत जहॉ मात्र 30 से 35 प्रतिशत जनसंख्या ही निवासरत है । स्पष्ट है कि वर्तमान में भारत में ऐसी उच्च शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता है जो वर्तमान स्तर से कहीं ज्यादा अच्छी हो व नवीन ज्ञान के प्रति समर्पित होते हुए ऊचाईयों को प्राप्त करें । योजनाबद्ध व्यूहरचता व ठोस प्रयत्न ही भारत को उच्च शिक्षा जगत में महत्व प्रदान कर सकते है । संक्षेप में भारतीय उच्च शिक्षण क्षेत्र के समक्ष निम्नांकित चुनौतियॉ विद्यमान है :

(1) प्रमुख रूप से बी–स्कूल के समक्ष ;kX; f'k{k.k lewg (Teaching Faculty) dh vR;Ur deh की चुनौती है, ये संस्थान लगभग 30 प्रतिशत योग्य शिक्षण समूह की कमी का सामना कर रहे जिसके 2020 तक 50 प्रतिशत हो जाने की संभावना है ।

(2) अधिकांश षिक्षण संस्थानों में ikB~;Øe v|ru ugha gSa पाठ्यक्रमों को समय–समय पर अद्यतन न किए जाने के कारण विद्यार्थी उभरते रोजगार बाजार में असफल हो जाते है एवं उनके पदांकन (**Placement**) की संभावनाएॅ ही कम हो जाती है ।

(3)xq.koRrkiw.kZ f'k{k.k 0;oLFkk को बनाए रखने की चुनौती ।

(4)विदेशों में विविध पाठ्यक्रमों व रोजगार के अवसरों की उपलब्धता तथा fons'kksa esa f'k{k.k ikus dju dh iofRr esa of) ।

(5) <kapkxr lqfo/kk,¡ जैसे कम्प्युटर लेब, इलेक्ट्रॉनिक लाईब्रेरी, शोध समर्थन का अभाव आदि भी भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्था के लिए चुनौती है ।

(7) भारत में उच्च शिक्षा में futh {ks= का योगदान 68% है जबकि 'kkldh; {ks= का योगदान मात्र 32% ही है ।

(8) विश्वविद्यालयों में कुलपति सहित शिक्षकों के पद राजनैतिक दबाब से प्रेरित होकर भरे जाते हैं।

(9) सेमेस्टर प्रणाली लागू होने से बाद से परीक्षा परिणाम घोशित करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है।

(10)2013–15 सत्र के लिए देश के सर्वप्रमुख बी. स्कूलों के एम.बी.ए. कोर्स प्रवेष IIM द्वारा इस खुलासे के बाद अधर में है कि कैट में 80% परीक्षार्थियों के ''अंकों में हेराफेरी'' की गई।

mPpf'k{kk esa iR;{k fons'kh fuos'k¼ **FDI)** dh vko';drk%&

वर्तमान समय यदि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो Hkkjrh; mPp f'k{kk dh lkekU; xq.koRrk mPp fdLe dh ugha gS A भारत में FDI कोई नई बात नहीं है । एशिया में सिंगापुर व चीन में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में FDI को बड़ी मात्रा में अनुमति दी गई है । उच्च शिक्षा में FDI की अनुमति से वर्तमान विश्वव्यवस्था में vkxs c<us व वर्तमान कार्यप्रणाली पर iquZfopkj का अवसर मिलता है । प्रतिस्पर्धा विकासोन्मुख बढ़ने से uokpkjksa'k में सहायता मिलती है, us'kuyukWyst deh'ku की 12 जनवरी 2007 की रिपोर्ट के सुझाव के अनुसार ''विदेशी निवेश को नीति बनाकर उच्च शिक्षा में इस प्रकार आमंत्रित करना चाहिए कि अच्छी षिक्षण संस्थाएं ही भारत में आने की प्रेरित हो व उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित हो एवं घरेलू उच्च शिक्षण संस्थाओं के वित के जो नियम है ,वे उन पर भी लागू हो ।'' यह कटु सत्य है कि भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में इस समय वित्त की कमी है घरेलू स्तर पर हम उच्च शिक्षा हेतु वित्त की उपलब्धता को सुगम नहीं बना सकते है । वित्त के अभाव को दूर करने के लिये FDI को उच्च शिक्षा के dqN pqus gq, {ks=ksa में विनियोजन की अनुमति दी जा सकती है।

mPp f'k{kk esa iR;{k fons'kh fuos'k **FDI** ds iHkko %&

किसी भी व्यवस्था को लागू करने से पूर्व उसके पक्ष व विपक्ष की तुलनात्मक स्थिति का आंकलन करना सबसे अधिक संगत युक्ति होती है । भारत में FDI के उच्च शिक्षा में प्रवेश के कारण जो सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव हो सकते है, उनका ऑकलन निम्नानुसार है :–

¼**A**½ lqiHkko %&

(1) विदेशी विश्वविद्यालय mUur f'k{k.k <kaps का उपयोग करने के आदि है, परिणामतः भारतीय विद्यार्थियों को वे वैसी ही ढॉचागत सुविधाएॅ प्रदान करेंगे जैसा कि वे स्वयं के देश में करते है ।

(2) नए शिक्षण संस्थान प्रारंभ किए जाने के कारण स्वाभाविक रूप से स्थानीय व्यक्तियों को uohu jkstxkj प्राप्त होंगे ।

(3) विदेशी वि.वि. के देश में स्थापित होने से ns'k esa ns'k dk Kku ¼izfrHkk½ cuk jgsxk क्योंकि विदेशों में शिक्षण प्राप्त करने की प्रवृत्ति कम होगी ।

(4) विदेशी वि.वि. द्वारा स्वाभाविक रूप से पढ़ने–पढाने की uohure rduhdh o fof/k;k का उपयोग किया जाएगा। परिणामतः भारत fo'oLrjh; ,l fo'ofo|ky;k dh LFkkiuk में सफलता प्राप्त कर सकता है जो उन्नत नवीनतम तकनीकों से युक्त हो ।

(5) भारतीय व विदेशी ज्ञान एवं विदेशी enk d vknku&iznku का प्रवाह बढ़ेगा ।

(6) Hkkjrh; f'k{kdk के लिए भी सुअवसर उपलब्ध होंगे।

(B) n"iHkko %&

(1) बढ़ती तीव्र प्रतिस्पर्धा आक्रामक रणनीति के परिणामस्वरूप Hkkjrh; f'k{k.k lLFkkuk dk ijkHko gkuk dh lHkouk cuxh A भारतीय शिक्षण संस्थानों के स्वअस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा ।

(2) jktxkj d u, volj ij Hkh i'u fpUg jgxk क्योंकि विदेशी संस्थान स्वयं के देश के स्टॉफ को प्राथमिकता देंगे । क्योंकि गुणवत्ता उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा।

(3)विदेशी संस्थान लाभों को अधिकतम करने के प्रयत्न में fo|kfFk;k d fgrk dh vogyuk करेंगे ।

(4)अधिकांश विदेशी वि.वि. प्रबंधन, तकनीक व विज्ञान के पाठ्यक्रमों मे ंशिक्षण में रूचि रखेंगे क्योंकि यह उनके लाभ व संतुष्टि का कारण रहेगा परिणामतः tulkekU; dh vko';drk ijh ugh gkxh A

fu"d"k ,o l>ko %&

यदि dM fu;=.k o fuxjkuh e FDI को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आमंत्रित किया जाता है तो यह कोई कठिन कार्य नहीं होगा । निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता से एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जा सकती है जो सभी संस्थानों को संचालित करें । doy mUgh ikB;Øek dk ijkHk dju dh vuefr nuk pkfg, ftudh ckt kj e ekx g] o f'k{kk d {k= e egRo'kkyh g A नियामक संस्थान व शासन दोनों के द्वारा ही नियमावली का निर्माण कर केवल उन्हीं विदेशी संस्थानों को भारत में अनुमति प्रदान करना चाहिए जिन्हें विदेशों में भी विदेशी शासन द्वारा मान्यता/अनुमति प्रदान की है इससे नकली वि.वि. के प्रवेश पर रोक लगी रहेगी।

दूसरी ओर सभी निजी, सार्वजनिक व fon'kh fo'ofo|ky;k dk viu okf"kd y[k&tk[k mu पाठ्यक्रमों के रखना चाहिए जो उनके द्वारा संचालित किए जा रहे है । oc lkbV पर उन्हें प्राप्त अनुमति, शुल्क ढॉचा, पाठ्यक्रम, सीटों की संख्या, स्टॉफ का विवरण व वित्त के स्त्रोत को स्पष्ट दर्शाना चाहिए अकादमिक क्षेत्र में त्वरित निर्णय इस प्रकार लिये जाने चाहिए कि ये संस्थान स्वयं को विश्वस्तर पर स्थापित कर सकें ।

संदर्भ ग्रंथ

1. U.G.C. & higereducation in india annual reports.
2. FICCI & EY: higereducation in india :12th five year plan¼ 2012&2017½
(3) प्रयिोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था विषेशांक 2012 व 2013